

[2025] 4 एस.सी.आर. 1921 : 2025 आई.एन.एस.सी. 570

सकीना सुल्तानाली सुनेसरा (मोमीन)

बनाम

शिया इमामी इस्माइली मोमीन जमात समाज और अन्य

(सिविल अपील सं.6681-6682 का 2023)

23 अप्रैल 2025

[विक्रम नाथ और प्रसन्न बी. वराले,* न्यायाधीश]

विचार के लिए मुद्दा

यह मुद्दा उठा कि क्या एक वादकारी जो पहले से ही मुकदमे में एक मुकदमाकार था, फिर भी एक डिक्री में सन्निहित समझौते के तथ्य या वैधता का विरोध करता है, तो क्या वह CPC के ऑर्डर XXIII नियम 3 के नियम के तहत ट्रायल कोर्ट में एप्लीकेशन देने तक ही सीमित है या सेक्शन 96(3) CPC के बावजूद सेक्शन 96 CPC के तहत पहली अपील कर सकता है।

मूलबिंदु

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 -एस. 96, Ord.XXIII आर.3, Ord.XLIII आर. 1ए(2), आर. 1 (एम)- मुकदमे का समझौता- मूल फरमानों से अपील-डिक्री के खिलाफ अपील में गैर-अपील योग्य आदेशों को चुनौती देने का अधिकार- मुकदमा लैंड के बिक्री विलेखों के संबंध में पक्षों के बीच विवाद-अपीलकर्ताओं के खिलाफ प्रतिवादी द्वारा मुकदमा जिसमें पक्षों के बीच समझौता जिसके परिणामस्वरूप पहली सहमति डिक्री होती है, उसके बाद दायर किए गए मुकदमे में एक और समझौता जिसके परिणामस्वरूप दूसरी सहमति डिक्री होती है- अपीलार्थी का मामला कि उसे किसी भी समझौते की कोई सूचना नहीं थी और धोखाधड़ी से प्राप्त दोनों सहमति डिक्री- अपीलार्थी ने दोनों फरमानों के खिलाफ ए. ओ. दायर किया।¹ए-स्थानांतरिती खरीदारों ने समानांतर ए. ओ.-उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश को दायर किया, जो बड़ी पीठ के फैसले पर कार्य करते हुए उस पक्ष को मुकदमा करने के लिए पहले Ord.XXIII आर. के प्रावधान का आह्वान करना चाहिए। आर3 और आर1ए स्वयं अपील का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं बनाता है, ए. ओ. को खारिज कर दिया गया- हस्तक्षेप:

आयोजित: हाई कोर्ट के निर्देश कानून की संरचनाको सही तरीके से लागू करते हैं और इसमें दखल की ज़रूरत नहीं है - बड़ी बेंच ने सही राय दी कि 1976 से ऐसे अपील अमान्य हैं - 1976 के संशोधन के बाद CPC दो अलग-अलग तरीकों से काम करता है

* लेखक

- अगर कोई व्यक्ति पहले से ही मुकदमे में पार्टी था, और इस बात से इनकार करता है कि कोई कानूनी समझौता हुआ था, तो CPC के अनुसार उस व्यक्ति को Ord.XXIII आर. 3 के नियम के तहत ट्रायल कोर्ट में वापस जाना होगा और उस कोर्ट से यह तय करने के लिए कहना होगा कि समझौता वैध है या नहीं - कोई ऐसा व्यक्ति जो मुकदमे में पार्टी नहीं था, लेकिन जिसके अधिकारों को सहमति डिक्री से नुकसान पहुँचा है, वह सेक्शन 96 के तहत पहली अपील में अपीलीय कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सिर्फ़ इजाज़त मिलने के बाद - Ord. XXIII आर. 3 का नियम वैकल्पिक नहीं है, यह रिकॉर्ड पर किसी भी पार्टी के लिए पहला और एकमात्र रास्ता है जो समझौते से इनकार करती है - Ord. XLIII r. 1-A अपील का कोई नया अधिकार नहीं बनाता है; यह सिर्फ़ एक अपीलकर्ता को, जो पहले से ही अपीलीय कोर्ट के सामने है, इस आधार पर डिक्री पर हमला करने में सक्षम बनाता है कि समझौता रिकॉर्ड नहीं किया जाना चाहिए था - जब समझौते के तथ्य पर कोई विवाद नहीं होता है, तो सेक्शन 96(3) में रोक पूरी तरह लागू होती है - तथ्यों के आधार पर, अपीलकर्ता ने कभी भी Ord.XXIII r. 3 के नियम का इस्तेमाल नहीं किया और इसके बजाय हटाए गए Ord.XLIII r. के आधार पर आदेशों के खिलाफ अपील दायर की। 1(एम)- यह नहीं कहा जा सकता है कि धोखाधड़ी एक सहमति डिक्री को एक सामान्य डिक्री में बदल देती है- धोखाधड़ी, अधिकार की कमी या अन्य दूषित करने वाले तत्व सटीक रूप से वे मामले हैं जिनकी जांच करने के लिए परंतुक निचली निचली अदालत को निर्देश देता है- जब तक कि उस मार्ग का अनुसरण नहीं किया जाता है, तब तक वैधानिक प्रतिबंध एस में है। 96(3) कार्यशील रहता है- अपीलकर्ता मुकदमों का एक पक्ष था और तीसरे पक्ष के लिए आरक्षित उचित उपाय नहीं कर सकता है। [पैरा 8,11-17]

उद्धृत केस कानून

पुष्पा देवी भगत बनाम राजिंदर सिंह और अन्य [2006] सप. 3 एससीआर 370:(2006) 5 एस. सी. सी. 566; बनवारी लाल बनाम चंदो देवी और एक अन्य [1992] सप।3 एससीआर 524:(1993) 1 एस. सी. सी. 581; त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह [2020] 4 एससीआर 650:2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 444; एच. एस. गौतम बनाम राम मूर्ति और एक अन्य [2021] 4 एससीआर 996:(2021) 5 एससीसी 241; एल. आर. एस. द्वारा से किशुन उपनाम राम किशुन (मृत)।(2005) 6 एस. सी. सी. 300; श्री सूर्या डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स बनाम

एन. शैलेश प्रसाद और अन्य [2022] 3 एस. सी. आर.1081:(2022) 5 एस. सी. सी. 736-संदर्भित।

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908; कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987

मुख्य शब्दों की सूची

सहमति डिक्री; समझौता; अपील का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं; समझौता दर्ज करने या अस्वीकार करने का आदेश; कोई अलग अपील नहीं; सहमति डिक्री के खिलाफ कोई अपील नहीं; धोखाधड़ी; समझौते की वैधता; डिक्री में सन्निहित समझौते की वैधता; पहली अपील; मुकदमे का समझौता; बिक्री विलेख; पहली सहमति डिक्री; दूसरी सहमति डिक्री; स्थानांतरिती खरीदार; अपील का स्वतंत्र अधिकार; तीसरे पक्ष के लिए आरक्षित उपाय।

मामला उत्पन्न हुआ

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: दीवानी याचिका सं. 6681-6682/2023 का 2017 के ए. एफ. ओ. संख्या 33 और 16 में अहमदाबाद में गुजरात उच्च न्यायालय के दिनांक 28.08.2019 के निर्णय और आदेश से

पार्टियों के लिए प्रस्तुतियाँ

अपीलकर्ता के लिए अधिवक्ता :

हुजेफा अहमदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अपूर्वा वकील, सुश्री अनुश्री प्रशित कपाड़िया, सुश्री रश्मि सिंह।

उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता:

राकेश उत्तमचंद्र उपाध्याय, सुश्री आरती उपाध्याय मिश्रा, हर्ष सोम, पंकज बी. वेलानी।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

निर्णय

प्रसन्न बी. वराले, न्यायाधीश

1. सकीना सुल्तानाली सुनेसरा ("अपीलार्थी") द्वारा दायर ये अपीलें 2017 के आदेश¹ संख्या 16 और 33 और संज्ञानात्मक ए. ओ. से अपील से उत्पन्न एक संदर्भ पर गुजरात उच्च न्यायालय की एक बड़ी पीठ द्वारा दिए गए दिनांकित निर्णय पर हमला करती हैं। उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि एक वादकारी जो पहले से ही मुकदमे का एक मुकदमा था, लेकिन सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908² के आदेश XXIII नियम 3 के तहत दर्ज किए गए समझौते के अस्तित्व या वैधता पर विवाद करता है, उसे पहले ट्रायल कोर्ट का

दरवाजा खटखटाना चाहिए। इसने अभिनिर्धारित किया कि सी. पी. सी. की खंड 96 के तहत पहली अपील केवल उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो मुकदमे के अभिलेख में नहीं था। उस घोषणा के बाद, उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने 06.09.2019 पर प्रत्येक लंबित एओ को रखरखाव की कमी के कारण खारिज कर दिया। इन अपीलों में संदर्भ निर्णय और परिणामी आदेश दोनों का विरोध किया गया है।

2. अपील को जन्म देने वाला तथ्यात्मक मैट्रिक्स इस प्रकार है:

2.1. सिद्धपुर, जिला पाटन, शहर सर्वेक्षण संख्या 321,322 और 323 में गैर-कृषि भूमि के तीन सन्निहित भाग, कुल मिलाकर 36,354 वर्ग किलोमीटर। उनकी मृत्यु पर वे उनकी विधवा नूरबानु, उनके बेटों सुल्तान और शौकताली (प्रतिवादी नं.3) और उनकी बेटी मुमताज (उत्तरदाता नं.7). सुल्तान ने अपने पीछे अपीलकर्ता और दो बच्चों, सलमा (प्रतिवादी नं. 5) और अल्ताफ (प्रतिवादी नं. 6) उनके कानूनी उत्तराधिकारियों के रूप में।

2.2. मुमताज ने हसन अली लाड के पक्ष में एक अपरिवर्तनीय जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी³ (प्रतिवादी नं.4) अपीलकर्ता सलमा, अल्ताफ और नूरबानु ने उनके पक्ष में दूसरे संयुक्त पी. ओ. ए. पर हस्ताक्षर किए।

2.3. 09.03.2007 पर, शौकत अली और हसन अली (अन्य सभी सह-मालिकों के लिए कार्य करने के लिए) 28,978.51 वर्ग किमी बेचने के लिए सहमत हुए। एम. ("सूट लैंड") दस व्यक्तियों को खुद को 'शिया इमामी इस्माइली' स्टाइल मुकदमाने के लिए। मोमीन जमात, सिद्धपुर '(प्रत्यर्थी सं.1) ₹2.51 करोड़ के लिए। केवल ₹15 लाख का भुगतान किया गया था; अगस्त 2011 में जारी समझौते को समाप्त करने वाला एक नोटिस।

2.4. 2012 तक, सलमा, अल्ताफ और मुमताज ने अपीलार्थी को व्यक्तिगत वकालतनामे प्रदान किए; तब तक मूल दस प्रस्तावित खरीदारों में से दो की मृत्यु हो चुकी थी। 10.01.2013 पर आठ जीवित बचे लोगों ने बेचने के समझौते और एक क्षतिपूर्ति बांड को रद्द करते हुए एक विलेख निष्पादित किया। अपीलकर्ता दोनों संयुक्त पी. ओ. ए., समझौते, रद्द करने के विलेख और बांड के मूल की अभिरक्षा का दावा करता है।

- 2.5. बाद में 2013 में, शौकत अली, सलमा, अल्ताफ और मुमताज ने अपीलार्थी के पक्ष में अपने अविभाजित हितों को त्याग दिया; चार उत्परिवर्तन प्रविष्टियों को प्रमाणित किया गया, जिससे वह एकमात्र दर्ज की गई मालिक बन गई।
- 2.6. अगस्त 2015 में, अपीलकर्ता ने तीन पंजीकृत बिक्री विलेख निष्पादित किए: दो दिनांकित 10.08.2015 3,272 वर्ग मी. और 6,385 वर्ग कि. मी.एम. से प्लेटिनम ट्रेडेक्स प्राइवेट लिमिटेड और एक दिनांकित 12.08.2015 6,567 वर्ग कि. मी.।एम. चार व्यक्तियों के लिए। उन व्यक्तियों में से दो स्वयं मूल दस विक्रेताओं में से थे।
- 2.7. बाद में 2015 में, हसन अली ने मूल विक्रेताओं में से दो के साथ, उस समूह के एक अन्य सदस्य, कुर्बन मोमीन को समाप्त लेनदेन को पुनर्जीवित करने के लिए राजी किया। 24.11.2015 पर उप-कलेक्टर, सिद्धपुर के समक्ष तीन राजस्व अपीलें दायर की गईं, जिसमें अपीलार्थी के बिक्री विलेखों को दर्शाने वाली उत्परिवर्तन प्रविष्टियों को चुनौती दी गई। अपीलकर्ता और शौकत अली को प्रतिवादी के रूप में उद्धृत किया गया था।
- 2.8. 2016 का नियमित दीवानी मुकदमा सं. 5 ("पहला मुकदमा") 5 जनवरी 2016 को दायर किया गया था, जिसमें एक घोषणा की मांग की गई थी कि प्रतिवादी सं. 1 के पास मुकदमा की जमीन थी। 21.01.2016 को, प्रतिवादी नंबर 1 ने कुरबान के ज़रिए, पाटन में रद्द किए गए एग्रीमेंट को लागू करवाने के लिए स्पेशल सिविल सूट नंबर 6 ऑफ़ 2016 ("दूसरा मुकदमा") दायर किया, जिसमें अपीलकर्ता और उसके दो बच्चों को हसन अली के ज़रिए दिखाया गया और शौकत अली को व्यक्तिगत रूप से शामिल किया गया।
- 2.9. 12.03.2016 को एक समझौता हुआ, जिस पर एक तरफ़ प्रतिवादी नंबर 1 और 2 (एक ट्रस्ट जो जमात का प्रतिनिधित्व करने वाला कहा जाता है) और दूसरी तरफ़ शौकत अली और हसन अली ने साइन किए। इसे 15.03.2016 को रिकॉर्ड किया गया, जिसके परिणामस्वरूप पहली सहमति डिक्री बनी। उस डिक्री पर भरोसा करते हुए, अभियोक्ता ने 23.04.2016 पर बिना शर्त पहला मुकदमा वापस ले लिया।
- 2.10. प्रतिवादी नं. 1 ने फिर 2016 का विशेष दीवानी मुकदमा संख्या 19 ("तीसरा मुकदमा") दायर किया, फिर से हसन अली द्वारा अपीलकर्ता और उसके बच्चों पर मुकदमा दायर किया। एक और समझौता दिनांकित 12.11.2016 ने 17.12.2016 पर एक दूसरी सहमति डिक्री का नेतृत्व किया।

- 2.11.अपीलकर्ता का कहना है कि उसे किसी भी समझौते की कोई सूचना नहीं थी और दोनों आदेश धोखाधड़ी से प्राप्त किए गए थे। इसलिए उसने पहले सहमति डिक्री के खिलाफ AO नंबर 16 ऑफ़ 2017 और दूसरे के खिलाफ AO नंबर 33 ऑफ़ 2017 दायर किया, जिसमें ऑर्डर XLIII रूल 1-A का हवाला दिया गया। ट्रांसफ़री खरीदारों ने समानांतर AO दायर किए।
- 2.12.उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने नियम 1-ए की शक्तियों पर परस्पर विरोधी खण्ड पीठ के विचारों को ध्यान में रखते हुए तीन प्रश्नों को एक बड़ी पीठ को भेजा, जिसमें कहा गया कि मुकदमे के एक मुकदमा को पहले आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधान का आह्वान करना चाहिए और यह कि नियम 1-ए स्वयं अपील का कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं बनाता है। उस घोषणा पर कार्रवाई करते हुए, एकल न्यायाधीश ने 06.09.2019 पर सभी एओ को खारिज कर दिया।
3. दिनांक 28.08.2019 की बड़ी पीठ के निर्णय से व्यथित होकर, अपीलकर्ता ने वर्तमान सिविल अपील दायर की है जिसमें दावा किया गया है कि सी. पी. सी. की खंड 96 प्रत्यक्ष प्रथम अपील की अनुमति देती है, भले ही समझौता स्वयं विवाद में हो।
4. अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हुज़ेफा अहमदी ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ संक्षेप में प्रस्तुत की हैं:
- 4.1. सी. पी. सी. में 1976 के संशोधन से पहले, आदेश XLIII नियम 1 (एम) ने आदेश XXIII नियम 3 के तहत एक समझौते को दर्ज करने या अस्वीकार करने के आदेश के खिलाफ आदेश से अपील की अनुमति दी। 1976 के संशोधन अधिनियम No.104 ने उस खंड को हटा दिया और उसी सांस में, आदेश XLIII नियम 1-ए (2) पेश किया। नया नियम चुनौती को डिक्री में स्थानांतरित कर देता है और खंड 96 के तहत पहली अपील को संरक्षित करता है; अब आदेश से कोई अलग अपील नहीं है।
- 4.2. विवादित निर्णय एक गैर-पक्ष को दो रास्ते प्रदान करता है (खंड 96 के तहत अनुमति के साथ समीक्षा या पहली अपील) लेकिन रिकॉर्ड पर एक पक्ष को आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधान के तहत एक आवेदन तक सीमित करता है। इस तरह का दृष्टिकोण नियम 1-ए (2) के उद्देश्य को विफल कर देता है, जो यह सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है कि किसी समझौते पर विवाद करने वाला कोई भी वादकारी इसे सीधे अपील में चुनौती दे सकता है।

4.3. अपीलकर्ता के वकील ने आगे कहा है कि पुष्पा देवी भगत बनाम राजिंदर सिंह और अन्य,⁴ बनवारी लाल बनाम चंदो देवी और अन्य⁵ और त्रिलोकी नाथ सिंह बनाम अनिरुद्ध सिंह⁶ के मामले में निर्धारित अनुपात पर उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ द्वारा सही और पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि बनवारी लाल (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने पैराग्राफ 9 और 13 में निम्नानुसार टिप्पणी की है:

"9. [.....] लेकिन जो संशोधन पेश किए गए हैं, उनके बाद आदेश 23 के नियम 3ए के दायरे में आने वाले मामलों में न तो समझौते को दर्ज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील और न ही मुकदमा दायर करने का उपाय उपलब्ध है। जैसा कि आदेश 43 के नियम 1ए (2) के तहत एक पक्ष को अधिकार दिया गया है, जो समझौते की रिकॉर्डिंग को चुनौती देता है, डिफेंडेंट के खिलाफ अपील को प्राथमिकता देते हुए इसकी वैधता पर सवाल उठाता है। संहिता की खंड 96 (3) ऐसी अपील के लिए बाधा नहीं होगी क्योंकि खंड 96 (3) उन मामलों में लागू होती है जहां समझौते या समझौते का तथ्य विवाद में नहीं है।

.....

13. [.....] यहां तक कि आदेश 43 के नियम 1 (एम) को भी हटा दिया गया है, जिसके तहत समझौता दर्ज करने वाले आदेश के खिलाफ अपील विचारणीय थी। एक समझौते को चुनौती देने वाला ऐसा पक्ष आदेश 23 के नियम 3 के प्रावधान के तहत एक याचिका दायर कर सकता है, या संहिता की खंड 96 (1) के तहत एक अपील दायर कर सकता है, जिसमें वह अब संहिता के आदेश 43 के नियम 1ए को देखते हुए समझौते की वैधता पर सवाल उठा सकता है।"

(जोर दिया गया)

4.4. एच. एस. गौतम बनाम राम मूर्ति और अन्य⁷, के मामले में बनवारी लाल (ऊपर) में अवलोकन पर भरोसा किया गया है और इसे मंजूरी दी गई है। उच्च न्यायालय ने पुष्पा देवी (उपरोक्त) के पैराग्राफ 17 में एक एकल सजा पर भरोसा किया कि "एकमात्र उपाय उस अदालत से संपर्क करना है जिसने समझौता दर्ज किया था।" वकील का तर्क है कि टिप्पणी इनक्यूरेड के अनुसार है: यह न तो बनवारी लाल (उपरोक्त) को नोटिस करता है और न ही एल. आर. एस. द्वारा एल. आर. एस.

बनाम बिहारी (मृत) द्वारा से किशुन उपनाम राम किशुन (मृत)⁸ में बाद के तीन-न्यायाधीशों की पीठ के फैसले को अलग करता है, जो स्पष्ट रूप से पहली अपील को मान्यता देता है जहां समझौता ही विवादित है।

5. दूसरी ओर, प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश उत्तमचंद्र उपाध्याय ने निम्नलिखित मुख्य प्रस्तुतियाँ की हैं:

5.1. प्रतिवादी उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष का समर्थन करते हैं कि मुकदमे का एक मुकदमा पहली अपील नहीं कर सकता है। एक सहमति डिक्री, वे आग्रह करते हैं, विरोध के रूप में काम करती है और केवल आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधान के तहत निचली अदालत में एक आवेदन द्वारा सवाल किया जा सकता है; खंड 96 (3) एक अपील को रोकती है और आदेश XLIII नियम 1 (एम) को हटाने से आदेश से अपील के पहले के रास्ते को हटा दिया जाता है।

5.2. पुष्पा देवी (उपरोक्त) पर भरोसा किया गया है, खासकर पैरा 17 पर, जिसमें संक्षेप में बताया गया है:

- “खंड 96 (3) को ध्यान में रखते हुए सहमति आदेश के खिलाफ कोई अपील विचारणीय नहीं है।”
- “ऑर्डर XLIII रूल 1 के क्लॉज़ (m) को हटाने के बाद समझौते को रिकॉर्ड करने वाले आदेश के खिलाफ कोई अपील बाकी नहीं रहती है।”

5.3. इस कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने त्रिलोकी नाथ सिंह (उपरोक्त) मामले में, पुष्पा देवी (उपरोक्त) और आर राजन्ना (उपरोक्त) पर विचार करने के बाद, यह माना कि 1976 के बाद किसी समझौते के फैसले को चुनौती देने के लिए “न तो अपील और न ही अलग से मुकदमा दायर किया जा सकता है”; ऑर्डर XLIII रूल 1 A(2) तभी लागू होता है जब ट्रायल कोर्ट ने पहले, ऑर्डर XXIII रूल 3 के नियम के तहत, यह तय किया हो कि कोई समझौता हुआ है या नहीं।

5.4. बनवारी लाल (उपरोक्त) और पुष्पा देवी (उपरोक्त) के बीच कोई भी साफ अंतर श्री सूर्या डेवलपर्स एंड प्रमोटर्स बनाम एन. शैलेश प्रसाद और अन्य⁹ में सुलझा लिया गया था, जिसमें यह पक्का किया गया कि डिक्री पास करने वाला कोर्ट ही समझौते की वैधता की जांच करने के लिए सही फोरम है। अपीलार्थी द्वारा उद्धृत बनवारी लाल (उपरोक्त) के पैराग्राफ 9 और 13 को उसी संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।

6. अभिलेख पर विचार करने और प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमारे सामने प्राथमिक प्रश्न यह है कि क्या एक वादकारी जो पहले से ही मुकदमे में एक

मुकदमाकार था, फिर भी एक डिक्री में सन्निहित समझौते के तथ्य या वैधता को चुनौती देता है, आदेश XXIII नियम 3 के परंतुक के तहत निचली अदालत के समक्ष एक आवेदन तक सीमित है या अपने चुनाव में, खंड 96 (3) के बावजूद सीपीसी की खंड 96 के तहत पहली अपील बनाए रख सकता है।

7. हमारा मानना है कि सबसे पहले सी. पी. सी. पर 1976 के संशोधन अधिनियम 104 के प्रभाव को देखना आवश्यक है। 01.02.1977 से पहले एक समझौता "रिकॉर्ड करने या रिकॉर्ड करने से इनकार करने" का आदेश आदेश XLIII नियम 1 (m) के तहत अपील योग्य था। संसद ने उस खंड को हटा दिया और उसी सांस में, चार सहयोगी प्रावधान पेश किए:

- **आदेश XXIII नियम 3 का प्रावधान और स्पष्टीकरण-** किसी समझौते के तथ्य या वैधता पर किसी भी आपति पर तत्काल और स्वयं निर्णय लेने के लिए निचली अदालत को बाध्य करना;
- **आदेश XXIII का नियम 3A-** एक समझौता डिक्री से बचने के लिए एक अलग मुकदमे को छोड़ मुकदमा;
- **ऑर्डर XLIII नियम 1A** - जो अपीलकर्ता पहले से ही किसी डिक्री के खिलाफ सक्षम अपील में है, उसे यह तर्क देने की अनुमति देता है कि समझौता "रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, या नहीं किया जाना चाहिए था"; और
- **धारा 96(3)** (जैसा कि फिर से नंबर दिया गया है) - "पार्टियों की सहमति से पारित" डिक्री के खिलाफ अपील पर रोक लगाता है।

8. हमारी राय में, इन प्रावधानों की व्याख्या काफी स्पष्ट और सुसंगत है। एक पक्ष जो समझौते को स्वीकार करता है, वह इसके लिए बाध्य है और अपील नहीं कर सकता (धारा 96 (3))। एक पक्ष जो समझौते से इनकार करता है, उसे पहले उस विवाद को निचली अदालत (आदेश XXIII नियम 3 का प्रावधान) के समक्ष उठाना चाहिए। एक नया मुकदमा अब संभव नहीं है (आदेश XXIII नियम 3A)। यदि, और केवल यदि, निचली अदालत आपति का निर्णय करता है और आक्षेपकर्ता के प्रतिकूल डिक्री पारित करता है, तो पहली अपील खंड 96 (1) के तहत होती है; उस अपील में अपीलकर्ता, आदेश XLIII नियम 1ए (2) के आधार पर, समझौते की रिकॉर्डिंग को चुनौती दे सकता है।

9. उपरोक्त पठन की पुष्टि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के एक समूह में की गई है। **बनवारी लाल (उपरोक्त)** में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि, 1976 के बाद, पीड़ित पक्ष के पास दो समवर्ती लेकिन क्रमिक उपचार हैं:

- विचारण न्यायालय के समक्ष आदेश XXIII नियम 3 के परंतुक के तहत एक आवेदन; या
- निचली अदालत द्वारा अपना निष्कर्ष दर्ज करने के बाद खंड 96 (1) के तहत पहली अपील।

10. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि **पुष्पा देवी (उपरोक्त)** मामले में इस कोर्ट ने, संशोधनों की समीक्षा करने के बाद, चार बातें कहीं, जिनमें मुख्य यह थी कि एक सहमति डिक्री तब तक बाध्यकारी होती है, "जब तक कि नियम 3 के नियम के तहत एक आवेदन पर उस कोर्ट द्वारा इसे रद्द न कर दिया जाए जिसने समझौता दर्ज किया था"। **पुष्पादेवी (उपरोक्त)** के प्रासंगिक पैरास को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"17. आदेश 23 के संशोधित प्रावधानों से उत्पन्न स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया जा सकता है:

(i) सी. पी. सी. की खंड 96 (3) में निहित विशिष्ट प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए सहमति आदेश के खिलाफ कोई अपील विचारणीय नहीं है।

(ii) नियम 1 आदेश 43 के खंड (एम) को हटाने के मद्देनजर समझौता दर्ज करने (या समझौता दर्ज करने से इनकार करने) के अदालत के आदेश के खिलाफ कोई अपील विचारणीय नहीं है।

(iii) समझौता डिक्री को इस आधार पर दरकिनार करने के लिए कोई स्वतंत्र मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता है कि नियम 3-ए में निहित बाधा को देखते हुए समझौता वैध नहीं था।

(iv) एक सहमति डिक्री एक अवरोध के रूप में काम करती है और वैध और बाध्यकारी होती है जब तक कि इसे उस अदालत द्वारा दरकिनार नहीं किया जाता है जिसने सहमति डिक्री पारित की है, नियम 3 आदेश 23 के प्रावधान के तहत एक आवेदन पर एक आदेश द्वारा।

इसलिए, किसी सहमति डिब्री के पक्षकार के पास ऐसी सहमति डिब्री से बचने का एकमात्र उपाय यह है कि वह उस कोर्ट में जाए जिसने समझौता दर्ज किया था और उसके आधार पर डिब्री दी थी, और यह साबित करे कि कोई समझौता हुआ ही नहीं था। उस स्थिति में, समझौता दर्ज करने वाली अदालत स्वयं इस सवाल पर विचार करेगी और फैसला करेगी कि क्या कोई वैध समझौता हुआ था या नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक सहमति डिब्री कुछ और नहीं बल्कि अदालत के अनुमोदन की मुहर के साथ अधिरोपित पक्षों के बीच अनुबंध है। सहमति आदेश की वैधता पूरी तरह से उस समझौते या समझौते की वैधता पर निर्भर करती है जिस पर यह किया जाता है। दूसरी प्रतिवादी, जिसने सहमति समझौते के फैसले को चुनौती दी थी, उसे इस स्थिति की पूरी जानकारी थी, क्योंकि उसने 21-8-2001 को सहमति फैसले को रद्द करने के लिए एक एप्लीकेशन दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि कानून के अनुसार कोई वैध समझौता नहीं हुआ था। महत्वपूर्ण रूप से, अन्य प्रतिवादियों में से किसी ने भी सहमति आदेश को चुनौती नहीं दी। स्वयं को सबसे अच्छी तरह से ज्ञात कारणों के लिए, दूसरे प्रतिवादी ने कुछ दिनों के भीतर (जो कि 27-8-2001 पर है) एक अपील दायर की और अदालत के समक्ष दायर आवेदन को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया जिसने सहमति डिब्री पारित की। संहिता की खंड 96 (3) में निहित एक्सप्रेस बार को ध्यान में रखते हुए, दूसरे प्रतिवादी द्वारा ऐसी अपील विचारणीय नहीं थी।

पुनः बिन्दु (ii)

18. आदेश 23 मुकदमों की वापसी और समायोजन से संबंधित है। नियम 3 मुकदमों के समझौते से संबंधित है, जिसका प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया है:

“3. मुकदमा का समझौता— जहां कोर्ट को यह संतोषजनक रूप से साबित हो जाता है कि कोई मुकदमा किसी कानूनी समझौते या सुलह से, जो लिखित में हो और जिस पर पार्टियों के दस्तखत हों, पूरी तरह या आंशिक रूप से सुलझा लिया गया है, या जहां प्रतिवादी मुकदमे की विषय-वस्तु के पूरे या किसी हिस्से के संबंध में वादी को संतुष्ट कर देता है, तो कोर्ट ऐसे समझौते, सुलह या संतुष्टि को रिकॉर्ड करने का आदेश देगा, और उसके अनुसार डिब्री पारित करेगा,

जहां तक यह मुकदमे की पार्टियों से संबंधित है, भले ही समझौते, सुलह या संतुष्टि की विषय-वस्तु मुकदमे की विषय-वस्तु के समान हो या न हो:"

उक्त नियम के दो भाग हैं। प्रथम भाग में यह प्रावधान है कि जहां यह न्यायालय की संतुष्टि के लिए साबित हो जाता है कि किसी मुकदमे को किसी वैध समझौते या समझौते द्वारा पूरी तरह से या आंशिक रूप से समायोजित किया गया है और मुकदमाकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है, तो न्यायालय ऐसे समझौते या समझौते को दर्ज करने का आदेश देगा और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगा। दूसरे भाग में यह प्रावधान है कि जहां कोई प्रतिअभियोक्ता मुकदमे के पूरे या विषय-वस्तु के किसी भी हिस्से के संबंध में अभियोक्ता को संतुष्ट करता है, वहां अदालत ऐसी संतुष्टि दर्ज करने का आदेश देगी और उसके अनुसार एक डिक्री पारित करेगी। नियम यह भी साफ़ करता है कि समझौता या एग्रीमेंट ऐसे मुद्दों या विवादों से संबंधित हो सकता है जो मुकदमे का विषय नहीं हैं और ऐसा समझौता या एग्रीमेंट न केवल मुकदमे के पक्षों के बीच, बल्कि दूसरों के बीच भी किया जा सकता है, लेकिन जो फैसला सुनाया जाएगा, वह मुकदमे के पक्षों तक ही सीमित रहेगा, भले ही एग्रीमेंट, समझौते या संतुष्टि का विषय मुकदमे के विषय के समान हो या नहीं। हालाँकि, हम इस अपील में नियम के इस पहलू से चिंतित नहीं हैं।

19. नियम 3 के पहले भाग और दूसरे भाग में क्या अंतर है? पहला भाग उन स्थितियों को संदर्भित करता है जहां एक समझौता या समझौता लिखित रूप में किया जाता है और पार्टियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं। उक्त समझौता या सुलह अदालत के सामने पेश किया जाता है। जब कोर्ट को यह यकीन हो जाता है कि मुकदमा पूरी तरह या आंशिक रूप से ऐसे लिखित समझौते या कॉम्प्रोमाइज़ से सुलझा लिया गया है, जिस पर पार्टियों ने साइन किए हैं और वह कानूनी है, तो पार्टियों के बीच तय बातों के आधार पर फैसला सुनाया जाता है। समझौते/समझौते में तय शर्तें बताई जाती हैं जिनके आधार पर दावा आपसी रियायतों या वादों से स्वीकार या एडजस्ट किया जाता है, ताकि इसमें शामिल पार्टियों को भविष्य में उनके वादे पूरे करने के लिए बाध्य किया जा सके और इसके अनुसार पास किए जाने वाले फैसले को लागू करके परफॉर्मेंस को लागू करवाया जा सके। दूसरी ओर, दूसरा भाग उन मामलों को संदर्भित

करता है जहां प्रतिअभियोक्ता ने दावे के बारे में अभियोक्ता को संतुष्ट किया है। यह अभियोक्ता को संतुष्ट करके हो सकता है कि उसके दावे को पूरा या निष्पादित करने की आवश्यकता नहीं है। यह आवश्यक दायित्व का निर्वहन या निष्पादन करके भी हो सकता है। जहां प्रतिअभियोक्ता मुकदमे के विषय-वस्तु के संबंध में अभियोक्ता को "संतुष्ट" करता है, वहां आगे कुछ भी नहीं किया जाना या लागू नहीं किया जाना है और इसके संदर्भ में पारित की जाने वाली डिक्री के किसी भी "प्रवर्तन" या "निष्पादन" का कोई सवाल ही नहीं है। आइए, इसे एक उदाहरण से समझते हैं, मान लीजिए कि एक लाख रुपये की वसूली के लिए एक मनी सूट दायर किया गया है। पक्षकार लिखित रूप में एक वैध समझौता या समझौता कर सकते हैं और उनके द्वारा हस्ताक्षरित हो सकते हैं, इस सहमति से कि प्रतिवादी एक निर्दिष्ट अवधि या निर्दिष्ट तरीके से एक लाख रुपये की राशि का भुगतान करेगा या इस बात पर सहमत हो सकता है कि प्रतिवादी द्वारा दावे के पूर्ण और अंतिम निपटान में केवल 75,000 रुपये की राशि का भुगतान किया जाएगा। ऐसा समझौता पहले हिस्से में आएगा और अगर प्रतिवादी वादा पूरा नहीं करता है, तो वादी एग्जीक्यूशन करके इसे लागू करवा सकता है। दूसरी ओर, मुकदमाकार न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते हैं कि प्रतिअभियोक्ता पहले ही एक लाख रुपये या 75,000 रुपये की राशि का पूर्ण और अंतिम संतुष्टि में भुगतान कर चुका है या कि वाद दावे का प्रतिअभियोक्ता द्वारा अदालत के बाहर पूरी तरह से निपटारा कर दिया गया है (या तो भुगतान की गई राशि का उल्लेख करके या इसका उल्लेख नहीं करके) या कि अभियोक्ता दावे पर दबाव नहीं डालेगा। यहां दायित्व पहले से ही प्रतिअभियोक्ता द्वारा किया जाता है या अभियोक्ता इस बात से सहमत है कि वह प्रदर्शन को लागू नहीं करेगा और प्रतिअभियोक्ता द्वारा कुछ भी नहीं किया जाना बाकी है। जैसा कि आदेश जो केवल दावे के उन्मूलन या संतुष्टि या दावे के अस्तित्व को दर्ज करता है, यह निष्पादन के अधिरोपण द्वारा "लागू" होने में सक्षम नहीं है, क्योंकि डिक्री के अनुसरण में प्रतिवादी द्वारा निष्पादित होने का कोई दायित्व नहीं है। इस तरह की "संतुष्टि" को पार्टियों द्वारा लिखित और हस्ताक्षरित समझौते या समझौते द्वारा व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है। यह अभियोक्ता या उसके वकील द्वारा एकतरफा प्रस्तुतिकरण द्वारा हो सकता है।

इस तरह की संतुष्टि दूसरे भाग के अंतर्गत आएगी। बेशक, जब प्रतिवादी द्वारा मुकदमे के दावे या विषय-वस्तु की ऐसी संतुष्टि होती है और मामला दूसरे भाग के अंतर्गत आता है, तब भी मुकदमाकारों को दावे/विषय-वस्तु की ऐसी संतुष्टि को लिखित रूप में कम करने और उस पर हस्ताक्षर करने से कुछ भी नहीं रोकता है। इन दोनों भागों में अंतर इस प्रकार है: जहाँ मामला दूसरे भाग के अंतर्गत आता है, वहाँ जो बताया जाता है वह विवाद को समाप्त करने वाली अदालत से बाहर एक पूर्ण कार्रवाई या समझौता है, और संतुष्टि दर्ज करने वाली परिणामी डिक्री, निष्पादन लागू करके लागू करने में सक्षम नहीं है। जहाँ मामला पहले भाग के अंतर्गत आता है, वहाँ एक वादा या वादे होते हैं जिन्हें पूरा करने या निष्पादित करने के लिए सहमति होती है, और इसे निष्पादन लागू करके लागू किया जा सकता है। जबकि पहले भाग के तहत आने वाले समझौते या समझौते केवल एक दस्तावेज या पार्टियों द्वारा हस्ताक्षरित लेखन के अन्य रूप से हो सकते हैं, दूसरे भाग के तहत आने वाले निपटान या संतुष्टि के संबंध में ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ मामला दूसरे भाग के अंतर्गत आता है, यह पर्याप्त है यदि अभियोक्ता या अभियोक्ता का वकील अदालत के समक्ष उपस्थित होता है और अदालत को सूचित करता है कि मुकदमे का विषय पहले ही सुलझा लिया गया है या संतुष्ट हो गया है।"

11. इसलिए रास्ता तय किया गया है: आदेश XXIII नियम 3 का प्रावधान वैकल्पिक नहीं है; यह रिकॉर्ड पर किसी भी पक्ष के लिए कॉल का विशेष पहला पोर्ट है जो समझौते से इनकार करता है। आदेश XLIII नियम 1-ए अपील का एक नया अधिकार नहीं बनाता है; यह केवल एक अपीलकर्ता को, जो पहले से ही अपील न्यायालय के समक्ष है, इस आधार पर डिक्री पर हमला करने में सक्षम बनाता है कि समझौता दर्ज नहीं किया जाना चाहिए था। जब समझौते की बात पर कोई विवाद नहीं होता, तो सेक्शन 96(3) में रोक पूरी तरह लागू होती है।
12. वर्तमान अपीलकर्ता स्पेशल सिविल सूट नंबर 6 ऑफ़ 2016 और स्पेशल सिविल सूट नंबर 19 ऑफ़ 2016 में रिकॉर्ड पर प्रतिवादी था। दोनों आदेश लिखित समझौते की शर्तों पर आधारित हैं जिन पर वकील द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जो निर्विवाद वकालतनामा रखते हैं। विधिवत अधिकृत वकील के हस्ताक्षर पक्ष के हस्ताक्षर होते हैं। इसलिए फरमान खंड 96 (3) के अर्थ के भीतर सहमति आदेश हैं। अपीलकर्ता ने कभी भी आदेश

XXIII नियम 3 के लिए परंतुक का आह्वान नहीं किया; इसके बजाय, उसने हटाए गए आदेश XLIII नियम 1 (एम) के आधार पर आदेशों से अपील दायर की। उच्च न्यायालय की बड़ी पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए सही कहा कि इस तरह की अपीलें 1976 से अक्षम हैं।

13. अपीलार्थी का यह निवेदन कि धोखाधड़ी के आरोप एक सहमति डिक्री को एक सामान्य डिक्री में बदल देते हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। धोखाधड़ी, अधिकार की कमी या अन्य दूषित करने वाले तत्व ठीक वे मामले हैं जिनकी जांच करने के लिए परंतुक निचली अदालत को निर्देश देता है। जब तक उस मार्ग का अनुसरण नहीं किया जाता है, तब तक सी. पी. सी. की खंड 96 (3) में वैधानिक प्रतिबंध लागू रहता है।
14. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाद के खरीदारों की उपस्थिति अपीलकर्ता की सहायता नहीं करती है। वे खरीदार कभी भी मुकदमों के पक्षकार नहीं थे; उन्होंने अनुमति के साथ, उच्च न्यायालय में पहली अपील की है, एक ऐसा पाठ्यक्रम जो सी. पी. सी. की खंड 96 (1) गैर-पक्षों को अनुमति देती है। इसके विपरीत, अपीलकर्ता मुकदमों का एक पक्ष था और तीसरे पक्ष के लिए आरक्षित उपचार का उपयोग नहीं कर सकता है। दोनों मुकदमों को अंततः एक लोक अदालत के समक्ष समझौता कर लिया गया। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की खंड 21 (2) लोक अदालत के फैसले की किसी भी अपील पर रोक लगाती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत सीमित पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र उपलब्ध है, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया है।
15. हम संतुष्ट हैं कि बड़ी पीठ ने सही दृष्टिकोण अपनाया। इसने देखा कि सी. पी. सी., 1976 के संशोधन के बाद, दो अलग-अलग तरीकों से काम करता है। यदि कोई व्यक्ति पहले से ही मुकदमे में मुकदमाकार था, और इस बात से इनकार करता है कि कोई वैध समझौता कभी हुआ है, तो सी. पी. सी. उस व्यक्ति से आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधान के तहत निचली अदालत में वापस जाने की अपेक्षा करता है और उस अदालत से यह तय करने के लिए कहता है कि समझौता वैध है या नहीं। दूसरी ओर, कोई ऐसा व्यक्ति जो मुकदमे में पार्टी नहीं था, लेकिन जिसके अधिकार सहमति डिक्री से प्रभावित हुए हैं, वह CPC की धारा 96 के तहत पहली अपील में अपीलीय कोर्ट में जा सकता है, लेकिन सिर्फ इजाजत मिलने के बाद। ऑर्डर XLIII रूल 1A कोई स्वतंत्र अपील नहीं बनाता है; यह सिर्फ इतना कहता है कि, जब कोई अपील कोर्ट के सामने आती है, तो अपील करने वाला यह तर्क दे सकता है कि समझौता रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, या

नहीं किया जाना चाहिए था। इस नज़र से देखें तो, हाई कोर्ट के निर्देश कानून के स्ट्रक्चर को सही तरीके से लागू करते हैं और उनमें दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है।

16. ऊपर दर्ज किए गए कारणों से, दीवानी अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।
17. गुजरात हाई कोर्ट की लार्जर बेंच का 28.08.2019 का फैसला, साथ ही एकल जज का 06.09.2019 का नतीजे वाला आदेश, दोनों को सही ठहराया जाता है।
18. अपीलकर्ता के लिए, यदि ऐसी सलाह दी जाती है, तो निचली अदालत के समक्ष सी. पी. सी. के आदेश XXIII नियम 3 के प्रावधान को लागू करने के लिए खुला है। हम ऐसे किसी भी आवेदन के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं करते हैं।
19. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।
20. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाएगा।

मामले का परिणाम: याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

¹मुख्यबिंदु तैयार किए गए: निधि जैन

-
- 1 एओ
 - 2 सीपीसी
 - 3 पीओए
 - 4 (2006) 5 एस. सी. सी. 566
 - 5 (1993) 1 एस. सी. सी. 581
 - 6 2020 एससीसी ऑनलाइन एससी 444
 - 7 (2021) 5 एस. सी. सी. 241
 - 8 (2005) 6 एससीसी 300
 - 9 (2022) 5 एस. सी. सी. 736